अतिरिक्त न्यायिक कार्यकारी पीड़ित परिवार एसोसिएशन और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

(याचिका (आपराधिक) संख्या 129/2012)

14 जुलाई, 2017

[मदन बी. लोकुर और उदय उमेश ललित, जे. जे.]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 21 और 32 नकली मुठभेड़ हत्याएं-मणिपुर राज्य में सशस्त्र बलों की वर्दी में पुलिस कर्मियों और कर्मियों द्वारा अत्यधिक बल का उपयोग या जवाबी बल प्रयोग-लिखित याचिका जिसमें आरोप लगाया गया है कि फर्जी मुठभेड़ों में 1528 लोग मारे गए-दस्तावेजों को किसी भी जांच का आदेश देने के लिए अपर्याप्त पाया गया-दस्तावेजों को पूरा करने के लिए निर्देश जारी करना-कथित 1528 में से 655 मौतों के संबंध में एकत्र की गई जानकारी, जिसमें मौतों की जांच जांच आयोगों, न्यायिक जांच, उच्च न्यायालय, एन. एच. आर. सी. और न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े आयोग द्वारा की गई थी और इन शिकायतों में एफ. आई. आर. दर्ज करने का निर्देश दिया गया था-मणिपुर में कथित अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं की जांच के लिए सी. बी. आई. को निर्देश जारी करना-मणिपुर पुलिस के अधिकारी जो विशेष जांच दल से जुड़े नहीं हैं, तब से विशेष जांच दल का गठन करें।

न्याय का प्रशासन-नकली मुठभेड़ों में हत्याएं-याचिका सभी उदाहरणों में, तीसरे पक्ष की, रिश्तेदारों की खुद को घटनाओं के लिए एक शांति देने के लिए-पकड़ की रखरखावः यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय किसी तीसरे पक्ष के कहने पर इस मुद्दे को नहीं उठा सकता है-न्याय तक पहुंच निश्चित रूप से एक मानव अधिकार है और इसे संवैधानिक योजना में एक विशेष स्थान दिया गया है जहां देश में बड़ी संख्या

में लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह प्रदान की जाती है-प्रत्येक नागरिक को न्याय तक पहुंच प्रदान करने और इसे सार्थक बनाने के लिए। इस न्यायालय ने अपना जनहित न्यायशास्त्र विकसित किया है-तत्काल याचिकाओं में, रिश्तेदार स्थानीय अदालतों में न्याय प्राप्त नहीं कर सकते थे और याचिकाकर्ताओं ने जनहित में अपना मुद्दा उठाया-संवैधानिक न्यायशास्त्र ऐसे व्यक्तियों पर दरवाजा बंद करने की अनुमति नहीं देता है और संवैधानिक दायित्व के लिए मृतक के अगले रिश्तेदार को न्याय और सहायता देने की आवश्यकता होती है।

क्षतिपूर्ति-नकली मुठभेड़ हत्या-क्षतिपूर्ति, क्या उचित राहत-आयोजितः दुर्भाग्यपूर्ण मौतों के लिए रिश्तेदारों को मुआवजे का भुगतान किए जाने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि मामले में आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं हो सकती है-रिश्तेदारों को उनकी पीड़ा के लिए मुआवजा दिया गया है और उन्हें तुरंत उनके पुनर्वास पर काबू पाने में सक्षम बनाया गया है-यह देश के कानून पर हावी नहीं हो सकता है. अन्यथा सभी जघन्य अपराध मौद्रिक मुआवजे के भुगतान के माध्यम से निपटाए जाएंगे-संवैधानिक न्यायशास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है और निश्चित रूप से इस तरह के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित या स्वीकार नहीं कर सकता है।

विलंब /देरी - फर्जी मुठभेड़ हत्याएं - कुछ पुरानी घटनाएं - जांच के लिए मुद्दों को फिर से खोलना - आयोजित: अपराध जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की मौत शामिल है जो संभवतः निर्दोष है, केवल एक चूक के कारण नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है समय की - यह राज्य का दायित्व था कि वह उचित समय पर और प्रत्येक घटना घटित होने के तुरंत बाद स्वत: संज्ञान लेकर गहन जांच कराए - केवल इसलिए कि राज्य ने कोई कार्रवाई नहीं की है और समय बीतने दिया है, वह ऐसा नहीं कर सकता किसी जांच को बाधित करने में देरी का फायदा।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-अपने संचार और दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन-एन. एच. आर. सी. की याचिका कि उसके संचार और दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन होना चाहिए, उसके द्वारा पारित आदेशों का प्रवर्तन होना चाहिए और इसके प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक प्रावधान होना चाहिए-आयोजितः एन. एच. आर. सी. का उद्देश्य आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी ढंग से सहायता करना और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए किसी भी तथ्यात्मक विवाद से बचना है-जब तक कि एन. एच. आर. सी. द्वारा निर्धारित संचार और दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तब तक मृतकों और सभी के मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और गरिमा केवल कागज पर ही रहेगी-एन. एच. आर. सी. द्वारा किए गए अनुरोध का तेजी से और अनुकूल रूप से सम्मान किया जाए और एन. एच. आर. सी. के प्रभावी कामकाज के लिए भारत संघ द्वारा विचार किया जाए।

मामले को स्थगित करते हुए, अदालत ने अभिनिर्धारित किया *:*

1.1 यह निवेदन कि कुछ घटनाएं काफी पुरानी हैं और इस समय जांच के लिए मुद्दों को फिर से खोलना उचित नहीं हो सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि कोई अपराध किया गया है, एक अपराध जिसमें संभवतः निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु शामिल है, तो इसे केवल समय बीतने के कारण नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह राज्य का दायित्व था कि वह स्वतः संज्ञान लेकर उचित समय पर और प्रत्येक घटना के तुरंत बाद पूरी तरह से जांच करे। केवल इसलिए कि राज्य ने कोई कार्रवाई नहीं की और समय जाने दिया, वह जांच को रोकने के लिए देरी का लाभ नहीं उठा सकता है। [पैरा 18] [378-ए-सी]

1.2 यह दलील कि स्थानीय दबाव था और जमीनी स्तर की स्थिति ऐसी थी कि अगर पूछताछ नागरिकों के पक्ष में और राज्य के खिलाफ होती तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी, खारिज कर दी जाती है। यदि मणिपुर राज्य में कानून का शासन टूट गया था, तो निश्चित रूप से भारत सरकार उचित कदम उठाने के लिए बाध्य थी। यह कहना कि सभी पूछताछ अनुचित और प्रेरित थीं, उस समय मणिपुर में अधिकारियों की स्वतंत्रता पर बहुत गंभीर आक्षेप लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। (पैरा 19) [378-डी-ई]।

1.3 यह निवेदन कि कई मामलों में मृतक के निकट संबंधियों ने इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया था और इस न्यायालय को किसी तीसरे पक्ष द्वारा दायर याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं है, खारिज कर दिया जाता है। न्याय तक पहुँच निश्चित रूप से एक मानव अधिकार है और इसे संवैधानिक योजना में एक विशेष स्थान दिया गया है जहाँ देश में बड़ी संख्या में लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह प्रदान की जाती है। इसका प्राथमिक कारण यह है कि समाज के कई वंचित वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच केवल एक सपना है। प्रत्येक नागरिक को न्याय तक पहुँच प्रदान करने और इसे सार्थक बनाने के लिए, इस न्यायालय ने अपना जनहित न्यायशास्त्र विकसित किया है जहाँ उपयुक्त मामलों में पत्र-याचिकाओं पर भी विचार किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में जनहित याचिकाओं के इतिहास ने यह तय किया है कि समाज के वंचित वर्ग और दलित जैसे बंधुआ मजदूर, तस्करी की गई महिलाएं, बेघर व्यक्ति, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार और अन्य लोग संवैधानिक अदालतों के दरवाजे खटखटा सकते हैं और न्याय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तत्काल याचिकाओं में ठीक यही हुआ है जहां रिश्तेदारों को स्थानीय अदालतों में भी न्याय नहीं मिल सका और याचिकाकर्ताओं ने जनहित में अपना मुद्दा उठाया है।

संवैधानिक न्यायशास्त्र ऐसे व्यक्तियों के लिए दरवाजे बंद करने की अनुमति नहीं देता है और संवैधानिक दायित्व के लिए मृतक के निकट संबंधियों को न्याय और सहायता देने की आवश्यकता है। [पैरा 20-21] [378-F-H; 379-A-B) ।

1.4 यह निवेदन कि दुर्भाग्यपूर्ण मौतों के लिए रिश्तेदारों को मुआवजा दिया गया है और इसलिए, मामले में आगे बढ़ना आवश्यक नहीं हो सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रिश्तेदारों को उनकी पीड़ा के लिए और उन्हें अपने नुकसान से तुरंत उबरने और उनके पुनर्वास के लिए मुआवजा दिया गया है। यह देश के कानून पर हावी नहीं हो सकता है, अन्यथा सभी जघन्य अपराधों का निपटारा मौद्रिक मुआवजे के भुगतान के माध्यम से किया जाएगा। संवैधानिक न्यायशास्त्र दस्तावेज़ इसकी अनुमति नहीं देते हैं और निश्चित रूप से इस तरह के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित या स्वीकार नहीं कर सकते हैं। [पैरा 22] [379-सी-डी]।

1.5 जहाँ तक एक विशेष जांच दल की नियुक्ति का संबंध है, यह सुझाव दिया गया था कि मणिपुर पुलिस के अधिकारी इससे जुड़े हो सकते हैं। मणिपुर पुलिस के किसी भी अधिकारी को संबद्ध करना उचित नहीं है, विशेष रूप से क्योंकि कुछ मामलों में मणिपुर पुलिस की भूमिका पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल के गठन का निर्देश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। इनमें से किसी भी मामले में मणिपुर पुलिस या संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी वर्दीधारी कर्मी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इसके विपरीत, मृतक के खिलाफ कानून के कथित उल्लंघन के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन परिस्थितियों में, मणिपुर पुलिस पर निष्पक्ष जांच करने के लिए निर्भर रहना अनुचित होगा, विशेष रूप से जब उसके अपने कुछ कर्मियों को नकली मुठभेड़ों में शामिल कहा जाता है और मणिपुर पुलिस ने मृतक के रिश्तेदारों के कहने पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।

उक्त मामलों की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच दल नियुक्त करना अधिक उपयुक्त कार्रवाई होगी। [पैरा 23-25] [379-D-H; 380-A-C]।

1.6 यह उचित होगा यदि केंद्रीय जांच ब्यूरो (या सी. बी. आई.) को इन नकली मुठभेड़ों या अत्यधिक या जवाबी बल के उपयोग की जांच करने की आवश्यकता है। सी. बी. आई. के निदेशक को निर्देश दिया जाता है कि वे आवश्यक एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए दी गई तीन तालिकाओं में उल्लिखित मामलों के रिकॉर्ड को देखने के लिए पांच अधिकारियों के एक समूह को नामित करें और 31 दिसंबर, 2017 तक इसकी जांच पूरी करें और जहां भी आवश्यक हो, आरोप पत्र तैयार करें। पूरा बुनियादी काम या तो जांच आयोगों द्वारा या न्यायिक जांच द्वारा या गुवाहाटी या मणिपुर उच्च न्यायालय या एनएचआरसी द्वारा पहले ही किया जा चुका है। यह विशेष जांच दल पर छोड़ दिया गया है कि वह कानून के अनुसार पहले से एकत्र की गई सामग्री का उपयोग करे। मणिपुर राज्य से विशेष जांच दल को पूरा सहयोग और सहायता देने की उम्मीद है। भारत संघ से उम्मीद की जाती है कि वह बिना किसी अनावश्यक बाधा या बाधाओं के जल्द से जल्द जांच पूरी करने के लिए विशेष जांच दल को पूरी सहायता प्रदान करेगा। [पैरा 26] [380-डी-एफ]।

1.7 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक एक दल नामित करेगा और इस न्यायालय को दो सप्ताह के भीतर इसकी संरचना के साथ-साथ किसी अन्य आवश्यकता के बारे में भी सूचित करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जाँच के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन याचिकाओं को निर्धारित अवधि के भीतर भी सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। [पैरा 48) (388-डी-ई]।

2.1 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत एन. एच. आर. सी. का गठन एक उच्च शक्ति वाले वैधानिक निकाय के रूप में किया गया है,

जिसके अध्यक्ष भारत के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं और हमेशा रहे हैं। अन्य में, उच्चतम न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हमेशा एनएचआरसी का सदस्य रहा है और रहा है। एन. एच. आर. सी. को अनिवार्य रूप से चार भूमिकाएँ निभानी हैं, अर्थात् मानवाधिकारों के रक्षक, सलाहकार, निगरानी और शिक्षक की। इसी क्षमता में एन. एच. आर. सी. ने प्रभावी जांच के माध्यम से मानवाधिकारों के रक्षक और निगरानीकर्ता के रूप में समय-समय पर हिरासत में मौत और बलात्कार से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग, पोस्टमॉर्टम परीक्षा की वीडियोग्राफी आदि सहित विभिन्न पहलुओं के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। [पारस 30,32] [381-एच; 382-ए-बी] ।

2.2 एन. एच. आर. सी. द्वारा यह निवेदन कि उसके सभी संचार और दिशानिर्देश केवल कागज पर बने हुए हैं और किसी भी राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं किए गए हैं; और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अच्छी गुणवत्ता वाली रिपोर्ट उपलब्ध हैं, दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, स्वीकार किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एन. एच. आर. सी. का इरादा आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली की अधिक प्रभावी ढंग से सहायता करना और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए किसी भी तथ्यात्मक विवाद से बचना है। ऐसा नहीं है कि केवल जीवित व्यक्तियों की गरिमा का सम्मान करने की आवश्यकता है, बल्कि मृतकों की गरिमा को भी उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। जब तक एन. एच. आर. सी. द्वारा निर्धारित संचार और दिशानिर्देशों (जो व्यापक और विस्तृत परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं) का पालन नहीं किया जाता है, तब तक मृतकों के प्रति सम्मान और गरिमा और सभी के मानवाधिकार केवल कागजों पर ही रहेंगे। [पैरा 38] [384-एफ-एच] ।

2.3 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 11 को पढ़ने से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि केंद्र सरकार पर्याप्त अधिकारी और कर्मचारी प्रदान करने के लिए

बाध्य है ताकि एन. एच. आर. सी. अपने कार्यों को कुशलता से कर सके। अपर्याप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण एन. एच. आर. सी. के सामने आने वाली कठिनाइयाँ और मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से चिंता की बात है। [पैरा 41] [385-एच; 386-ए]

2.4 यह देखते हुए कि इस तरह के एक उच्च शक्ति वाले निकाय-एन. एच. आर. सी. ने इस न्यायालय में दायर हलफनामों और लिखित प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी कठिनाइयों को सामने लाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दुर्भाग्य से एक दांत रहित बाघ बन गया है। इस संबंध में एन. एच. आर. सी. द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध का भारत संघ द्वारा शीघ्रता से और अनुकूल रूप से सम्मान किया जाना चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए अन्यथा एन. एच. आर. सी. के लिए प्रभावी ढंग से काम करना असंभव हो जाएगा और देश में मानवाधिकारों के सम्मान के संबंध में टालने योग्य आलोचना को भी आमंत्रित करेगा, भारत संघ को एन. एच. आर. सी. की चिंताओं पर ध्यान देने और उन्हें जल्द से जल्द और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दूर करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 44][387-ए-बी] ।

2.5 एन. एच. आर. सी. के आदेशों का पालन न करने के संदर्भ में, एन. एच. आर. सी. द्वारा यह भी लाया गया है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के लिए उसके द्वारा जारी निर्देशों का कभी-कभी पालन नहीं किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां मुआवजे के भुगतान के लिए एन. एच. आर. सी. द्वारा दिए गए निर्देशों को मणिपुर राज्य द्वारा लागू नहीं किया गया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन मणिपुर राज्य की ओर से पेश वकील का आश्वासन स्वीकार किया जाता है कि एन. एच. आर. सी. द्वारा दिया गया मुआवजा जल्द ही मृतक के परिजन को दिया जाएगा। सभी राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे समय-समय पर उत्पन्न होने वाले मुआवजे और अन्य मुद्दों के संबंध में एन. एच. आर. सी. द्वारा

जारी निर्देशों का पालन करें। यदि देश के लोग मानवाधिकारों से वंचित हैं या उन्हें लागू नहीं कर सकते हैं, तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। [पैरा 45-46] [387-C-E] ।

2.6 एन. एच. आर. सी. की वेबसाइट से यह पुष्टि की गई है कि सभी राज्यों में मानवाधिकार आयोग नहीं हैं। जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियम की धारा 21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान करता है, इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है। हालाँकि, संविधान के भाग III के प्रावधानों, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 के सार के अनुसार, प्रत्येक राज्य को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा कोई निर्देश जारी करना उचित नहीं है, विशेष रूप से तत्काल रिट याचिकाओं में। लेकिन, सभी राज्य सरकारों के ध्यान में यह लाना अनिवार्य महसूस किया जाता है कि यदि जल्द से जल्द राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है तो यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक छोटा कदम होगा। [पैरा 47] [387 एफ-एच]

2.7 एन. एच. आर. सी. द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट लाने में विफलता पर निराशा व्यक्त की जाती है; एन. एच. आर. सी. की वेबसाइट के अवलोकन से पता चलता है कि नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2012-2013 की है। तब से कई साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है-इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि बाद की वार्षिक रिपोर्टों को तैयार करने या उन पर विचार करने का चरण क्या है। उम्मीद है कि मानवाधिकारों के महत्व को देखते हुए, एनएचआरसी की वार्षिक रिपोर्ट उचित अभियान के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। [पैरा 48] (388-बी-सी]।

नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ। (1998) 2 एस. सी. सी. 109: [1997] 5 पूरक। एस. सी. आर. 469; भारती तमांग बनाम भारत संघ और अन्य। (2013) 15 एस. सी. सी. 578: [20131 14 एस. सी. आर. 525; आर.

सोधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। (1994) पूरक। 1 एस. सी. सी. 143; राम देव चौहान बनाम बानी कांत दास (2010) 14 एस. सी. सी. 209-संदर्भित।

मामला विधि संदर्भ

[1997]5 पूरक एससीआर 469	संदर्भित	पैरा 1
[2013]14 एससीआर 525	संदर्भित	पैरा 24
[1994] पूरक 1 एससीसी 143	संदर्भित	पैरा 25
[2010] 14 एससीसी 209	संदर्भित	पैरा 31

आपराधिक मूल अधिकारिता : याचिका (आपराधिक)संख्या 129/2012

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

याचिका (आपराधिक) संख्या 445/2012

डॉ. मेनका गुरुस्वामी, गोविंद मनोहरन, न्यायमित्र। मुकुल रोहतगी, ए. जी., कॉलिन गोंजाल्विस, श्रीमती वी. महाना, वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री ज्योति मेंदिरत्ता, सुश्री ओलिविया बैंग। वारेप्पम बसंत कुमार, अशोक कुमार सिंह, आर. बाला, सुनील जे. मैथ्यूज, एम. के. मारोरिया। राजीव नंदा, सुश्री बीनू टम्टा, बी. के. प्रसाद, प्रभास बजाज, प्रणव कुमार, रोहित राठी, सुश्री सबा इकबाल सिद्दीकी, सुनील मेथू, सुश्री अनन्या मिश्रा, पी. के. डे। पंकज पांडे, हिमांशु शेखर, नरेश कुमार गौर, निरंजन सनम, मानव वोहरा, स्वाधा शंकर, राणा रंजीत सिंह, रवीश सिंह, सत्य मित्रा, सुश्री मृण्मयी साहू, सुश्री पिंकी बेहरा, सुश्री शोभा, बोनी मेहरा, अधिवक्ता उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय मदन बी. लोकुर, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. वर्तमान याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि संघ के सशस्त्र बलों की वर्दी में पुलिस कर्मियों और कर्मियों द्वारा फर्जी मुठभेड़ों में 1528 लोग मारे गए थे। 8 जुलाई, 2016 के अपने फैसले और आदेश द्वारा हमने नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण का सम्मानपूर्वक पालन किया। संविधान पीठ ने कहा कि वर्दीधारी कर्मियों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग या जवाबी बल प्रयोग के आरोप के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इस घटना की गहन जांच की आवश्यकता है। हमारी राय थी कि सेना प्रमुख की 'क्या करें और क्या न करें' और 'दस आज्ञाएं' भी इस नैतिकता में विश्वास करती हैं और इस सिद्धांत को स्वीकार करती हैं। हालांकि, कानून में प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हमने पाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की तत्काल किसी भी जांच का आदेश देने के लिए दस्तावेज अपर्याप्त थे और इसलिए उन्हें निर्देश दिया कि वे दस्तावेज को पूरा करें जो यह दर्शाता है कि क्या आरोप किसी न्यायिक जांच या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई जांच या जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत की गई जांच पर आधारित थे।

2. तब से याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा एक सारणीबद्ध बयान दायर किया गया है और इस बयान को विद्वान न्यायमित्र द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और भारत संघ या मणिपुर राज्य द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। इसलिए हम अपने सामने सारणीबद्ध कथन के आधार पर आगे बढ़ते हैं।

3. याचिकाकर्ता रिट याचिकाओं में कथित 1528 मौतों में से 655 मौतों के संबंध में जानकारी एकत्र करने में सक्षम हुए हैं। इसका विभाजन इस प्रकार है -

क्रम संख्या	विवरण	मामलों की संख्या
1	जांच आयोग के मामले	35
2	न्यायिक जांच और उच्च न्यायालय के मामले	37
3	एनएचआरसी मामले	23
4	लिखित शिकायत वाले मामले	170
5	मौखिक शिकायत वाले मामले	78
6	चश्मदीद गवाहों के साथ मामले	134
7	परिवार ने मामलों का दावा किया	178
	कुल गणना	655

4. हमने लिखित शिकायतों, मौखिक शिकायतों और चश्मदीद गवाहों के खातों के साथ-साथ परिवार द्वारा दावा किए गए मामलों के संबंध में दिए गए सारणीबद्ध बयान का अध्ययन किया है, लेकिन पाया है कि एक साधारण आरोप लगाए जाने के अलावा, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) दर्ज करके या संबंधित उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन. एच. आर. सी.) में शिकायत करके कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आरोप बहुत सामान्य प्रकृति के होने के कारण, हम इन लिखित शिकायतों, मौखिक शिकायतों, चश्मदीद गवाहों के मामलों और परिवार द्वारा दावा किए गए मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में कुछ समय के लिए कोई निर्देश देना उचित नहीं समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक आरोप की जांच होनी चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि हम व्यक्तिगत मामलों से नहीं बल्कि संवैधानिक आपराधिक कानून से संबंधित एक प्रणालीगत या संस्थागत प्रतिक्रिया से निपट रहे हैं।

जाँच आयोग द्वारा जाँच की गई मौतें

5. जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत गठित आयोगों द्वारा दी गई रिपोर्टों में 35 मौतों के संबंध में हम पाते हैं कि दो मौतें इस प्रकार हैंः रिट याचिका में एल. डी. रेंगतुईवान और एन. संजीता देवी का उल्लेख नहीं किया गया था। हम इन दोनों मामलों के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करते हैं।

6. जहाँ तक थंगजाम मनोरमा की मृत्यु का संबंध है, मुद्दे इस न्यायालय में सिविल अपील संख्या 65-69/2015 में लंबित हैं और इसलिए हम इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं।

7. जहाँ तक शेष 32 मृत पीड़ितों का संबंध है, हम पाते हैं कि स्वतंत्र जांच आयोगों ने मणिपुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (जैसा भी मामला हो) के कर्मियों के खिलाफ अत्यधिक बल या जवाबी बल के उपयोग के लिए प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं। हमारी राय में, इन 32 व्यक्तियों की मौत के संबंध में उपयुक्त पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक प्रथम दृष्टया से अधिक मामला बनाया गया है। हम इन मामलों में एफ. आई. आर. दर्ज करने का निर्देश देते हैं। 'पूछताछ मामलों के आयोग' का विवरण तालिका-1 में नीचे दिया गया है।

क्रम संख्या	पीड़ित का नाम (कुल 35)	अधिसुचना दिनांक	यूनिट
1	एल. डी. आरकंगतुई वान	16.03.2005	डबल्यूपी में नहीं
2	थंगजाम मनोरमा	?	एससी मे पेंडिंग
3	एन. संजीता देवी	06.12.2003	डबल्यूपी में नहीं

4-14	अमोम राजन मेटेई व 10 अन्य	04.07.2001	सीआरपीएफ़
15-19	मेजर शिमरिंगम शैजा व 4 अन्य	?	मणिपुर पुलिस
20-21	थौडम मुनिन्द्रो सिंह व अन्य	27.12.1996	मणिपुर पुलिस
22	ओइनम औंगबी अमीना देवी	06.04.1996	सीआरपीएफ़
23-35	अंगोम रघुमानी व 12 अन्य	15..06.1985	सीआरपीएफ़

(तालिका 1)

न्यायिक जांच और उच्च न्यायालय द्वारा मौतों पर विचार किया गया

8. 'न्यायिक जांच और उच्च न्यायालय के मामलों' के संबंध में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अत्यधिक या जवाबी बल प्रयोग के माध्यम से नकली मुठभेड़ों में 37 लोगों की मौत के आरोपों पर रिट याचिकाओं पर विचार किया था और कुछ मामलों में न्यायिक जांच का आदेश दिया था।

9. दो रिट याचिकाएं अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित हैं और हम संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (चाहे वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय हो या मणिपुर उच्च न्यायालय) से अनुरोध करते हैं कि वे रिट याचिकाओं का तेजी से निपटान करें यदि उनका पहले ही निपटारा नहीं किया गया है।

10. एक रिट याचिका [डब्ल्यू.पी. (आपराधिक) संख्या 103/2009] को खारिज कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय को लगाए गए आरोपों में कोई तथ्य नहीं मिला और इसलिए इस मामले को बंद माना जा सकता है।

11. दो अन्य रिट याचिकाओं के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है और हम इसे जांच दल पर छोड़ देते हैं जिसे हम सही तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए नियुक्त करने का प्रस्ताव करते हैं।

12. शेष रिट याचिकाओं के संबंध में, उच्च न्यायालय ने मृतक के निकट संबंधियों को मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसका अर्थ है कि इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के विपरीत एक फर्जी मुठभेड़ या अत्यधिक या जवाबी बल के उपयोग का प्रथम दृष्टया अधिक मामला पाया गया है। हम इन मामलों में एफ. आई. आर. दर्ज करने का निर्देश देते हैं।इन रिट याचिकाओं का विवरण तालिका-II में दिया गया है।

एन. एच. आर. सी. द्वारा इन मामलों में एफ. आई. आर. में हुई मौतों की जांच की गई।

13. नकली मुठभेड़ों या अत्यधिक या जवाबी बल के उपयोग के परिणामस्वरूप एन. एच. आर. सी. को 20 मौतों की सूचना दी गई थी। इनमें से 7 शिकायतें एन. एच. आर. सी. के समक्ष लंबित हैं। हम एनएचआरसी से इन शिकायतों पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का अनुरोध करते हैं।

14. दो शिकायतों के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है और हम एनएचआरसी से इन शिकायतों के परिणाम का पता लगाने के लिए इसे जांच दल पर छोड़ देते हैं।

15. शेष शिकायतों में, एन. एच. आर. सी. ने मृतक के निकट संबंधियों को मुआवजा दिया है जिसका अर्थ है कि एक नकली मुठभेड़ या अत्यधिक या जवाबी बल के उपयोग का प्रथम दृष्टया अधिक मामला है। हम इन शिकायतों के संबंध में एफ. आई. आर. दर्ज करने का निर्देश देते हैं।

16. जिन शिकायतों में एन. एच. आर. सी. चाप का संदर्भ दिया गया है, उनका विवरण तालिका-III में दिया गया है।

न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े आयोग द्वारा जांच

17. यह याद किया जा सकता है कि न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े (इस न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश) की अध्यक्षता वाले आयोग द्वारा पहले छह मामलों पर विचार किया गया था और जिसका उल्लेख हमारे पहले के आदेशों में मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन मामलों में भी एक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और उचित जांच के बाद, कानून के अनुसार आगे के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हम इन मामलों के एफआईआर पंजीकरण का भी निर्देश देते हैं।

प्रस्तुतियाँ और विचार

18. विद्वान महान्यायवादी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि कुछ घटनाएं काफी पुरानी हैं और इस समय जांच के लिए मुद्दों को फिर से खोलना उचित नहीं हो सकता है। हम विद्वान महान्यायवादी से सहमत नहीं हैं। यदि कोई अपराध किया गया है, एक अपराध जिसमें संभवतः निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु शामिल है, तो इसे केवल समय बीतने के कारण नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह भी स्वीकार्य नहीं है कि संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून होने के कारण, यह राज्य का दायित्व था कि वह स्वतः संज्ञान लेते हुए उचित समय पर और प्रत्येक घटना के तुरंत बाद पूरी तरह

से जांच करे। केवल इसलिए कि राज्य ने कोई कार्रवाई नहीं की है और समय दिया है, वह जांच को रोकने के लिए देरी का लाभ नहीं उठा सकता है।

19. विद्वान महान्यायवादी द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि स्थानीय दबाव थे और जमीनी स्तर की स्थिति ऐसी थी कि अगर पूछताछ नागरिकों के पक्ष में और राज्य के खिलाफ पक्षपातपूर्ण होती तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। यह केवल एक प्रस्तुति है जिसे नोट किया जाता है और अस्वीकार कर दिया जाता है। यदि मणिपुर राज्य में कानून का शासन टूट गया था, तो निश्चित रूप से भारत सरकार उचित कदम उठाने के लिए बाध्य थी। यह सुझाव देना कि सभी पूछताछ अनुचित और प्रेरित थीं, उस समय मणिपुर में अधिकारियों की स्वतंत्रता पर बहुत गंभीर आक्षेप लगा रहा है, जो हमें नहीं लगता कि बिल्कुल भी उचित है।

20. यह भी प्रस्तुत किया गया कि कई मामलों में मृतक के निकट संबंधियों ने इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया था और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें किसी तीसरे पक्ष द्वारा दायर याचिका पर विचार करना चाहिए। चूँकि रिश्तेदारों ने स्वयं इन घटनाओं पर मौन रखा था, इसलिए वास्तव में इस न्यायालय के लिए किसी तीसरे पक्ष के कहने पर इस मुद्दे को उठाने का कोई अवसर नहीं है। हम इस निवेदन को भी अस्वीकार करते हैं।

21. न्याय तक पहुँच निश्चित रूप से एक मानवाधिकार है और इसे हमारी संवैधानिक योजना में एक विशेष स्थान दिया गया है जहाँ देश में बड़ी संख्या में लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह प्रदान की जाती है। इसका प्राथमिक कारण यह है कि समाज के कई वंचित वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच केवल एक सपना है। प्रत्येक नागरिक को न्याय तक पहुँच प्रदान करने और इसे सार्थक बनाने के लिए, इस न्यायालय ने अपना जनहित न्यायशास्त्र विकसित किया है जहाँ उपयुक्त मामलों में

पत्र-याचिकाओं पर भी विचार किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में जनहित याचिकाओं के इतिहास ने यह तय किया है कि समाज के वंचित वर्ग और दलित जैसे बंधुआ मजदूर, तस्करी की गई महिलाएं, बेघर व्यक्ति, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार और अन्य लोग हमारी संवैधानिक अदालतों के दरवाजे खटखटा सकते हैं और न्याय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वर्तमान याचिकाओं में ठीक यही हुआ है जहां रिश्तेदारों को स्थानीय अदालतों में भी न्याय नहीं मिल सका है और याचिकाकर्ताओं ने जनहित में अपना मुद्दा उठाया है। हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र हमें ऐसे व्यक्तियों के लिए दरवाजे बंद करने की अनुमति नहीं देते हैं और हमारे संवैधानिक दायित्व के लिए हमें मृतक के निकट संबंधियों को न्याय और सहायता देने की आवश्यकता है।

22. विद्वान महान्यायवादी द्वारा अंततः यह प्रस्तुत किया गया कि दुर्भाग्यपूर्ण मौतों के लिए रिश्तेदारों को मुआवजा दिया गया है और इसलिए मामले में आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। हम सहमत नहीं हो सकते। रिश्तेदारों को उनकी पीड़ा के लिए और उन्हें अपने नुकसान से तुरंत उबरने और उनके पुनर्वास के लिए मुआवजा दिया गया है। यह देश के कानून पर हावी नहीं हो सकता है, अन्यथा सभी जघन्य अपराधों का निपटारा मौद्रिक मुआवजे के भुगतान के माध्यम से किया जाएगा। हमारा संवैधानिक न्यायशास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है और हम निश्चित रूप से इस तरह के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित या स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

विशेष जांच दल

23. जहाँ तक एक विशेष जाँच दल की नियुक्ति का संबंध है (जिसे हमने ऊपर बताया है), हमें यह सुझाव दिया गया था कि मणिपुर पुलिस के अधिकारी संबद्ध हो सकते हैं। हम मणिपुर पुलिस के किसी भी अधिकारी को संबद्ध करना उचित नहीं

समझते हैं, विशेष रूप से क्योंकि कुछ मामलों में मणिपुर पुलिस की भूमिका पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।

24. भारती तमांग बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपराधिक अभियोजन बिना किसी कमी के चलाया जाए, इस न्यायालय के आदेशों के तहत एक विशेष दल का गठन किया जा सकता है। नतीजतन, जिन मामलों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उनकी जांच के लिए एक विशेष जांच दल के गठन का निर्देश देने में हमें कोई झिझक नहीं है। इस स्तर पर यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि हमें सूचित किया गया था कि किसी भी मामले में मणिपुर पुलिस या संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी वर्दीधारी कर्मी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इसके विपरीत। मृतक के खिलाफ कानून के कथित उल्लंघन के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन परिस्थितियों में हमारे लिए निष्पक्ष जांच करने के लिए मणिपुर पुलिस पर निर्भर रहना अनुचित होगा, विशेष रूप से जब इसके अपने कुछ कर्मियों को नकली मुठभेड़ों में शामिल कहा जाता है और मणिपुर पुलिस ने मृतक के रिश्तेदारों के कहने पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।

25. आर. एस. सोधी बनाम यू. पी. राज्य मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः --

"हमारा मानना है कि चूंकि आरोप स्थानीय पुलिस कर्मियों के खिलाफ लगाए गए हैं, इसलिए केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी एक स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपना वांछनीय होगा ताकि मृतक के रिश्तेदारों सहित सभी संबंधित आश्वस्त महसूस कर सकें कि एक स्वतंत्र एजेंसी मामले को देख रही है और यह जांच की विश्वसनीयता का अंतिम परिणाम देगा। हालाँकि स्थानीय पुलिस ईमानदारी से जाँच कर सकती है, लेकिन उसमें विश्वसनीयता की कमी होगी क्योंकि आरोप उनके खिलाफ हैं। "

यह उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए है कि ऊपर उल्लिखित मामलों की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच दल नियुक्त करना अधिक उपयुक्त कार्रवाई होगी।

26. इन मुद्दों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद, हमारी राय है कि यह उचित होगा यदि केंद्रीय जांच ब्यूरो (या सी. बी. आई.) को इन फर्जी मुठभेड़ों या अत्यधिक या जवाबी बल के उपयोग की जांच करने की आवश्यकता है। तदनुसार, सी. बी. आई. के निदेशक को ऊपर दी गई तालिकाओं में उल्लिखित मामलों के अभिलेखों को देखने, आवश्यक एफ. आई. आर. दर्ज करने और 31 दिसंबर, 2017 तक इसकी जांच पूरी करने और जहां भी आवश्यक हो, आरोप पत्र तैयार करने के लिए पांच अधिकारियों के एक समूह को नामित करने का निर्देश दिया जाता है। पूरा बुनियादी काम या तो जांच आयोगों द्वारा या न्यायिक जांच द्वारा या गुवाहाटी या मणिपुर उच्च न्यायालय या एनएचआरसी द्वारा पहले ही किया जा चुका है। हम कानून के अनुसार पहले से एकत्र की गई सामग्री का उपयोग करने के लिए इसे विशेष जांच दल पर छोड़ देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मणिपुर राज्य विशेष जांच दल को पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेगा। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि भारत संघ बिना किसी अनावश्यक बाधाओं या बाधाओं के जल्द से जल्द जांच पूरी करने के लिए विशेष जांच दल को पूरी सहायता प्रदान करेगा। सी. बी. आई. के निदेशक दल को नामित करेंगे और दो सप्ताह के भीतर हमें इसकी संरचना के बारे में सूचित करेंगे।

एनएचआरसी-एक दाँत रहित बाघ

27. हमने श्री गोपाल सुब्रमण्यम को भी सुना है। कुछ मुद्दों के संबंध में एन. एच. आर. सी. की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनके आधार पर पहले हमारे सामने यह अनुरोध किया गया था कि एन. एच. आर. सी. एक दांत रहित बाघ के अलावा और कुछ नहीं है।

28. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून का शासन अरस्तू के समय से ही एक आधार पर रखा गया है। हाल ही में डाइसी ने कानून के शासन के घटकों पर भी व्याख्या की है और अब यह उम्मीद की जाती है कि सभी आधुनिक लोकतांत्रिक क्षेत्राधिकार कानून के शासन को मध्यस्थता कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ लोगों के लिए उपलब्ध मार्गदर्शक प्रकाश और ढाल के रूप में स्वीकार करते हैं। जहाँ तक हमारा संबंध है, कानून के शासन को भी हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र की मूल संरचना के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है। निस्संदेह, मानवाधिकारों का संरक्षण और संरक्षण कानून के शासन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है।

29. इसे ध्यान में रखते हुए, साथ ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 लागू किया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण काफी महत्वपूर्ण है और मानवाधिकार न्यायशास्त्र में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों के महत्व को स्वीकार करता है। उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार हैः -

" 1. भारत 16 दिसंबर, 1966 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाए गए नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा का एक पक्ष है। उपरोक्त समझौतों में सन्निहित मानवाधिकारों को संविधान द्वारा काफी हद तक संरक्षित किया गया है।

2. हालाँकि, मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों को लेकर देश और विदेश में चिंता बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए, बदलती सामाजिक वास्तविकताओं और अपराध और हिंसा की प्रकृति में उभरते रुझानों को ध्यान में रखते हुए, सरकार न्याय के प्रशासन के मौजूदा कानूनों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों की समीक्षा कर रही है, ताकि

उनमें अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाई जा सके और स्थिति से निपटने के लिए कुशल और प्रभावी तरीके तैयार किए जा सकें।

3. मानवाधिकारों पर मुख्यमंत्री सम्मेलन, देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित संगोष्ठियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठकों जैसे विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। इन चर्चाओं में व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान विधेयक को संसद के समक्ष लाया जाता है।

30. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत एन. एच. आर. सी. का गठन एक उच्च शक्ति वाले वैधानिक निकाय के रूप में किया गया है, जिसके अध्यक्ष भारत के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं और हमेशा रहे हैं। अन्य में, उच्चतम न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एनएचआरसी का सदस्य है और हमेशा रहा है।

31. राम देव चौहान बनाम बानी कांत दास में इस न्यायालय ने माना कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में परिभाषित नहीं किए गए 'मानवाधिकार' शब्दों को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में बहुत व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया है और ये मानवाधिकार भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। इस न्यायालय को रिपोर्ट के पैराग्राफ 47-49 में इस संबंध में यही कहना थाः

"मानवाधिकार बुनियादी, अंतर्निहित, अपरिवर्तनीय और अविभाज्य अधिकार हैं जिनके लिए एक व्यक्ति केवल अपने मानव जन्म के आधार पर हकदार है। वे ऐसे अधिकार हैं जिन्हें अधिकार के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। सभ्य देश का संविधान और कानून उन्हें मान्यता देते हैं क्योंकि वे प्रत्येक मनुष्य का अभिन्न अंग हैं। यही कारण है कि कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध प्रत्येक लोकतांत्रिक देश ने अपने प्रवर्तन और सुरक्षा के लिए तंत्र को लागू किया।

मानवाधिकार सार्वभौमिक प्रकृति के हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 10-12-1948 पर अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (इसके बाद यूडीएचआर के रूप में संदर्भित) कुछ सार्वभौमिक अधिकारों के पालन को मान्यता देती है और मानव अधिकारों के रूप में व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, और इन्हें किसी व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा और विकास के लिए समान और अविभाज्य और आवश्यक के रूप में स्वीकार और स्वीकार किया जाता है। नतीजतन, हालांकि "मानवाधिकार" शब्द को यू. डी. एच. आर. में परिभाषित नहीं किया गया है, मानवाधिकारों की प्रकृति और सामग्री को उनमें निहित अधिकारों से समझा जा सकता है।

संभवतः ऐसे बुनियादी अधिकारों के व्यापक विस्तार पर विचार करते हुए, 1993 के अधिनियम में "मानवाधिकारों" की परिभाषा को बहुत व्यापक रूप से रखा गया है ताकि संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं में सन्निहित और भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जाने योग्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित सभी अधिकारों को शामिल किया जा सके। इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को संविधान के तहत या किसी अंतर्राष्ट्रीय वाचा के तहत या किसी कानून के तहत कुछ अधिकारों की गारंटी दी गई है, और उसे इस तरह के अधिकार से वंचित किया जाता है, तो यह उसके मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और एनएचआरसी के पास इसकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र है। "

32. यह प्रस्तुत किया गया था (और हम सहमत हैं) कि एन. एच. आर. सी. की अनिवार्य रूप से चार भूमिकाएँ हैं, अर्थात् मानवाधिकारों के रक्षक, सलाहकार, निगरानी और शिक्षक की। इसी क्षमता में एन. एच. आर. सी. ने प्रभावी जांच के माध्यम से मानवाधिकारों के रक्षक और निगरानीकर्ता के रूप में समय-समय पर हिरासत में मौत और बलात्कार से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग, पोस्टमॉर्टम परीक्षा की वीडियोग्राफी आदि सहित विभिन्न पहलुओं के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

33. 14 दिसंबर, 1993 को एन. एच. आर. सी. ने देश भर की कानून और व्यवस्था एजेंसियों को 24 घंटे के भीतर हिरासत में मौतों और बलात्कार से संबंधित मामलों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। (उस समय, पुलिस कार्रवाई में मौत को 'हिरासत में मौत' के तहत वर्गीकृत किया गया था)।

34. कुछ साल बाद, 10 अगस्त, 1995 को एन. एच. आर. सी. ने सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र भेजा जिसमें उन्हें तथ्यों के साथ छेड़छाड़ से बचने के लिए 1 अक्टूबर, 1995 से पोस्टमॉर्टम परीक्षाओं की वीडियो-फिल्मिंग शुरू करने की आवश्यकता के बारे में सलाह दी गई। इसके बाद 27 मार्च, 1997 को एन. एच. आर. सी. द्वारा सभी मुख्यमंत्रियों को भेजे गए एक अन्य पत्र में सिफारिश की गई कि सभी राज्य एन. एच. आर. सी. द्वारा तैयार किए गए "मॉडल ऑटोप्सी फॉर्म" और "पूछताछ के लिए अतिरिक्त प्रक्रिया" को अपनाएं जो विशेषज्ञों और संयुक्त राष्ट्र मॉडल ऑटोप्सी प्रोटोकॉल के साथ चर्चा पर आधारित था। यह सुनिश्चित करने के लिए था कि सभी जानकारी संबंधित अधिकारी द्वारा एकत्र की गई थी और बिना किसी देरी के एनएचआरसी को आपूर्ति की गई थी।

35. 29 मार्च 1997 को एन. एच. आर. सी. ने मुठभेड़ से होने वाली मौतों के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की सिफारिश करते हुए दिशानिर्देश जारी किए। अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी किः

i. मृत्यु को पुलिस स्टेशन में एक उपयुक्त रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

ii. इसे संज्ञेय अपराध के रूप में माना जाना चाहिए और जांच शुरू की जानी चाहिए।

iii इसकी जाँच राज्य सी. आई. डी. जैसी एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए, न कि उसी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा।

iv दोषसिद्धि में समाप्त होने वाले मामलों में पीड़ित के आश्रितों को मुआवजे पर विचार किया जाना चाहिए।

36. इन दिशानिर्देशों को अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए 2 दिसंबर, 2003 को संशोधित और प्रसारित किया गया था, क्योंकि राज्य नियमित रूप से एन. एच. आर. सी. को मुठभेड़ में होने वाली मौतों के बारे में सूचित नहीं कर रहे थे, जिससे सांख्यिकीय डेटा प्रभावित हो रहा था। संशोधित दिशानिर्देशों में पिछले दिशानिर्देशों के अलावा निम्नलिखित बड़े बदलाव शामिल हैंः

क. यदि पुलिस के खिलाफ कोई विशिष्ट शिकायत की गई थी, तो एक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।

ख़. प्रत्येक मुठभेड़ में हुई मौत की मजिस्ट्रेट जांच अब अनिवार्य थी;

ग. इसके लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक को पुलिस कार्रवाई में हुई सभी मौतों के विवरण का 6-मासिक विवरण एन. एच. आर. सी. को भेजने की आवश्यकता थी।

37. जैसा कि कोई भी उम्मीद कर सकता है, राज्यों द्वारा दिशानिर्देशों का निरंतर गैर-अनुपालन किया गया, जिससे एनएचआरसी के लिए 12 मई, 2010 को दिशानिर्देशों को और संशोधित करना और प्रसारित करना आवश्यक हो गया, जिसमें पिछले दिशानिर्देशों के अलावा निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन शामिल थेः

क़. मजिस्ट्रेट जांच को 3 महीने के भीतर पूरा करने की आवश्यकता थी।

ख़. पुलिस कार्रवाई में हर मौत की सूचना 48 घंटों के भीतर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा एन. एच. आर. सी. को दी जानी थी;

ग. जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 3 महीने के भीतर एन. एच. आर. सी. को दूसरी रिपोर्ट भेजी जानी थी, जिसमें पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट, इन्क्वेस्ट रिपोर्ट, बैलिस्टिक रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट जांच के निष्कर्ष शामिल थे।

ये दिशा-निर्देश वर्तमान में लागू हैं।

38. एन. एच. आर. सी. द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि इसके सभी संचार और दिशानिर्देश केवल कागजों पर बने हुए हैं और किसी भी राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं किए गए हैं। एन. एच. आर. सी. का निवेदन था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अच्छी गुणवत्ता वाली रिपोर्ट उपलब्ध हैं, दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। हम इस निवेदन से सहमत हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि एन. एच. आर. सी. का इरादा आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली की अधिक प्रभावी ढंग से सहायता करना और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए किसी भी तथ्यात्मक विवाद से बचना है। ऐसा नहीं है कि केवल जीवित व्यक्तियों की गरिमा का सम्मान करने की आवश्यकता है, बल्कि मृतकों की गरिमा को भी उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। जब तक एन. एच. आर. सी. द्वारा निर्धारित संचार और दिशानिर्देशों (जो व्यापक और विस्तृत परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं) का पालन नहीं किया जाता है, तब तक मृतकों के प्रति सम्मान और गरिमा और हम सभी के मानवाधिकार केवल कागजों पर ही रहेंगे।

एनएचआरसी से संबंधित अन्य मुद्दे

39. एन. एच. आर. सी. द्वारा जारी किए गए संचार और दिशानिर्देशों के लिए चिंता की कमी या उन पर ध्यान न दिए जाने के अलावा, एन. एच. आर. सी. के सामने कठिनाई यह है कि भले ही आधे-अधूरे मन से अनुपालन हो, लेकिन राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट भेजने में अस्पष्ट देरी होती है; रिपोर्टों की गुणवत्ता निश्चित

रूप से सही नहीं होती है और जैसा कि अपेक्षित थाः कभी-कभी रिपोर्टों में कुछ कॉलम खाली छोड़ दिए जाते हैं और अन्य अवसरों पर कुछ दस्तावेज अवैध होते हैं आदि। एन. एच. आर. सी. के अनुसार, यह सब इसके कुशल कामकाज में बाधा डालता है और पीड़ित व्यक्तियों के मानवाधिकारों के कार्यान्वयन में देरी का कारण बनता है।

40. यह भी प्रस्तुत किया गया कि एन. एच. आर. सी. को दैनिक आधार पर बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती हैं और अक्सर एक दिन में 450 शिकायतें प्राप्त होती हैं। एन. एच. आर. सी. पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए अनुरोध कर रहा है, लेकिन अतिरिक्त कर्मचारी प्रदान करने के बजाय, कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है। इसके परिणामस्वरूप मौजूदा स्टाल पर बोझ बढ़ गया है इस संदर्भ में, हमारा ध्यान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 11 की ओर आकर्षित किया गया था जो इस प्रकार हैः

"11. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी- (1) केंद्र सरकार आयोग को उपलब्ध कराएगी -

(क) भारत सरकार के सचिव के पद का एक अधिकारी जो आयोग का महासचिव होगा; और

(ख) पुलिस महानिदेशक के पद से कम के अधिकारी के अधीन ऐसे पुलिस और जांच कर्मचारी और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी जो आयोग के कार्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए आवश्यक हों।

(2) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन, आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।

(3) उप-धारा (2) के तहत नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जाएं।

41. उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार पर्याप्त अधिकारी और कर्मचारी प्रदान करने के लिए बाध्य है ('उपलब्ध कराएगी') ताकि एन. एच. आर. सी. अपने कार्यों को कुशलता से कर सके। अपर्याप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण एन. एच. आर. सी. के सामने आने वाली कठिनाइयाँ और मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से चिंता की बात है।

42. एन. एच. आर. सी. का सामान्य निवेदन यह है कि इसके संचार और दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन होना चाहिए, इसके द्वारा पारित आदेशों का प्रवर्तन होना चाहिए और एन. एच. आर. सी. द्वारा की गई सिफारिशों और इसके प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक प्रावधान पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

43. एन. एच. आर. सी. ने अपने काम के बोझ में बदलाव का संकेत देते हुए निम्नलिखित तालिका हमारे सामने रखी है और इसकी सावधानीपूर्वक जांच से स्पष्ट रूप से कर्मचारियों की संख्या के संबंध में उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदमों का संकेत मिलता है।

जाँच प्रभाग द्वारा स्वीकृत शक्ति और 2014-15 के दौरान कार्य भार की तुलना 1995-96 में की गई है।			
	वर्तमान (31.03.2015)	पिछले	% बढ़त / घटत
स्वीकृत कर्मचारी	49**	59*	-16.94% स्टाफ स्ट्रेन्थ मे कमी

कुल शिकायतें प्राप्त प्रतिवर्ष	1,14,167	7843	1455% बढ़त
जाँच	53	13	407% बढ़त
हिरासत में मौत के मामले	5496	444	1237% बढ़त
तथ्यान्वेषी मामले	1851	706	262% बढ़त
रैपिड एक्शन सेल (आरएसी) के मामले 2007 के बाद शुरू हुए)	120 (अकेले पिछले तीन महीनों में 100 से अधिक मामले जोड़े गए)	निल	120 गुना

तालिका -IV

44. यह देखते हुए कि इस तरह के एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय ने इस न्यायालय में दायर हलफनामों और लिखित प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी कठिनाइयों को सामने लाया है, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दुर्भाग्य से एक दांत रहित बाघ बन गया है। हमारा स्पष्ट मत है कि इस संबंध में एन. एच. आर. सी. द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध का भारत संघ द्वारा शीघ्रता से और अनुकूल रूप से सम्मान किया जाना चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए अन्यथा एन. एच. आर. सी. के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करना असंभव हो जाएगा और हमारे देश में मानवाधिकारों के सम्मान के संबंध में टालने योग्य आलोचना को भी आमंत्रित करेगा। हम भारत संघ को एनएचआरसी की चिंताओं पर ध्यान देने और उन्हें जल्द से जल्द और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दूर करने का निर्देश देते हैं।

45. एन. एच. आर. सी. के आदेशों का पालन न करने के संदर्भ में, एन. एच. आर. सी. द्वारा यह भी लाया गया है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के लिए उसके द्वारा जारी निर्देशों का कभी-कभी पालन नहीं किया जाता है। हमने ऊपर दी गई तालिका-III में देखा है कि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां मुआवजे के भुगतान के लिए एन. एच. आर. सी. द्वारा दिए गए निर्देशों को मणिपुर राज्य द्वारा लागू नहीं किया गया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन हम मणिपुर राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील के इस आश्वासन को स्वीकार करते हैं कि एन. एच. आर. सी. द्वारा दिया गया मुआवजा जल्द ही मृतक के निकट संबंधियों को दिया जाएगा।

46. हम उम्मीद करते हैं कि सभी राज्य सरकारें मुआवजे और समय-समय पर उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दों के संबंध में एन. एच. आर. सी. द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगी। अगर हमारे देश के लोग मानवाधिकारों से वंचित हैं या उन्हें लागू नहीं कर सकते हैं, तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा।

राज्य मानवाधिकार आयोग

47. हमें सूचित किया गया है कि सभी राज्यों में मानवाधिकार आयोग नहीं हैं और इसकी पुष्टि एन. एच. आर. सी. की वेबसाइट से की गई है। जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है, इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है। हालाँकि, हमारी राय में, हमारे संविधान के भाग III के प्रावधानों, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के सार के अनुसार, प्रत्येक राज्य को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करने की आवश्यकता है, लेकिन हम राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करने के लिए राज्य सरकारों को विशेष रूप से वर्तमान रिट याचिकाओं में कोई

निर्देश जारी करना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन, हम सभी राज्य सरकारों के ध्यान में यह लाना अनिवार्य महसूस करते हैं कि यदि जल्द से जल्द राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है तो यह हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की दिशा में एक छोटा कदम होगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

48. हमें अपनी वार्षिक रिपोर्ट लाने में एन. एच. आर. सी. की विफलता पर अपनी निराशा व्यक्त करनी चाहिए। एनएचआरसी की वेबसाइट के अवलोकन से पता चलता है कि नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2012-2013 की है। तब से कई साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है-हमें पता नहीं है कि बाद की वार्षिक रिपोर्टों को तैयार करने या उन पर विचार करने का चरण क्या है। हम आशा व्यक्त करते हैं कि मानवाधिकारों के महत्व को देखते हुए, एनएचआरसी की वार्षिक रिपोर्ट उचित अभियान के साथ उपलब्ध कराई जाएगी।

आदेश

1. जैसा कि पहले से ही निर्देश दिया गया है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक एक दल नामित करेगा और हमें दो सप्ताह के भीतर इसकी संरचना के साथ-साथ किसी अन्य आवश्यकता के बारे में भी सूचित करेगा। अनुपालन के लिए तीन सप्ताह के तुरंत बाद इन मामलों को सूचीबद्ध करें।

2. इन याचिकाओं को जनवरी, 2018 के दूसरे सप्ताह में भी सकारात्मक रूप से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए ताकि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के लिए हमारे निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

मामला स्थगित कर दिया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक हेमंत सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक एवं अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।